

उन्हें सफलता
से मारो और
मुकुराहट से
दफना दो।

- अज्ञात

विचार-प्रवाह

देहरादून बृहस्पतिवार 28 मई 2020

पेज थ्री

www.page3news.in

दुनिया के लिए मिसाल

याद रहे, इस मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले हम अपने इलाके के अकेले देश नहीं हैं। कोरोना से जारी इस जंग में जान बचाने के मामले में पूरा साउथ एशिया दुनिया के लिए मिसाल बना हुआ है।

रश्मि शाह।

भारत में कोरोना संक्रमितों की संख्या एक लाख की रेखा पार कर गई है। इस बीच थोड़ी राहत की बात यही है कि संसाधनों की सीमा के बावजूद हमारे यहाँ मौतों की संख्या विकसित दर्शों से कम है। यद रहे, इस मोर्चे पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले हम अपने इलाके के अकेले देश नहीं हैं। कोरोना से जारी इस जंग में जान बचाने के मामले में पूरा साउथ एशिया दुनिया के लिए मिसाल बना हुआ है।

गरीबी, बेरोजगारी, साफ-सफाई और ऐसे तमाम मानकों पर दुनिया का पिछड़ा हिस्सा माने जाने वाले दक्षिण एशियाई देश कोरोना से होने वाली मौतों में पश्चिम के अमीर समाजों से कहीं बेहतर साबित हो रहे हैं।

तो फ्रांस में यह 15.2 है, ब्रिटेन में 14.4 तो इटली में 14 और स्पेन में 11.9। अमेरिका में सीएफआर ज्यादातर यूरोपीय देशों से कम है लेकिन वहाँ भी यह 6 फीसदी है। इनके मुकाबले भारत में यह 3.3 फीसदी है। जबकि पाकिस्तान में 2.2 फीसदी, बांग्लादेश में 1.5 फीसदी और श्रीलंका में महज 1 फीसदी है।

इस चमत्कार को समझाने के लिए की जा रही माथापच्ची के क्रम में कई व्याख्याएं सामने आई हैं। पहली संभावना यहीं व्यक्त की गई कि आंकड़े सही नहीं होंगे। मगर जांच-पड़ताल के बाद इस बात पर लगभग आम राय कायम हो गई कि आंकड़े बिल्कुल सटीक न हुए तो भी उनमें इतनी गड़बड़ी नहीं हो सकती कि प्रतिशत इस कदर

पलटा हुआ दिखने लगे। दूसरी व्याख्या यह सामने आई कि साउथ एशिया के सारे देशों में ज्यादातर आबादी युवा है।

यूरोपीय देशों में कोरोना के चलते मौत का शिकार हुए लोगों में बड़ी संख्या ओल्डएज होम में रहने वाले बुजुर्गों की है।

एक संभावना यह भी जताई जा रही है कि इन देशों में लोगों को बचपन से ही इतने टीके पड़ चुके होते हैं कि शरीर की प्रतिरोधी शक्ति बढ़ जाती है। परिवर्ती देशों में टीकी और मरलिया जैसी बीमारियां हैं ही नहीं तो वहाँ टीके भी नहीं लगाए जाते। यह भी कि बचपन से तरह-तरह की बीमारियों और गंदगी के संपर्क में रहने के कारण

दोरों जीवाणुओं और विषाणुओं से टकराने का अनुभव ले चुका शरीर अनजान बीमारियों के सामने भी वैसा अनाढ़ी नहीं साबित होता जैसा विकसित दुनिया के निवासियों का हो रहा है। कुछ लोग दक्षिण एशिया की कम मौतों का रहस्य यहाँ की जलवाया में खोज रहे हैं। उनके मुताबिक ज्यादा गर्मी में संक्रमण शुरू होने के कारण वायरस यहाँ अपनी पूरी सदृशक शक्ति नहीं दिखा पा रहा।

बहरहाल, ये व्याख्याएं हमारे लिए निश्चित होने की गुंजाइश नहीं बनातीं क्योंकि इनमें से एक भी रुस पर लागू नहीं होती, जहाँ सीएफआर 1 प्रतिशत से भी कम है। हमें अपनी तैयारियां उस दौर को ध्यान में रखकर ही करनी होंगी, जब कोरोना के भयंकरतम रूप से हमारे सामना होगा।



कटोरी का रहस्य

अशोक बोहरा।

राजा भिखारी के पैरों में गिर गया और उससे कहा, "मुझे माफ कर दें। पर आप यहाँ से जाने से पहले मुझे एक बात बताएं। इस भीख की कटोरी का रहस्य क्या है? इसमें सबकुछ गायब कैसे हो गया?" भिखारी हंसने लगा। उसने कहा, "यह आदमी की इच्छाओं से बना है। मैंने इसे आदमी की इच्छाओं से बनाया है जो कभी नहीं भरता। चाहे इसे कितना भी भरे, इसमें सबकुछ गायब हो जाता है।" यह कटोरा इंसान के मन की इच्छाओं से बना है और इसमें तुम दुनियाभर के राज्य ही क्यों ना डाल दो पर इसमें सबकुछ गायब हो जाता है और यह खाली रह जाता है। यहाँ तक कि एलेक्जेंडर भी खाली हाथ मरा था और एडोल्फ हिटलर भी भिखारी की तरह मरा। केवल वह लोग जो चाहतों को पूरा करना जानते हैं, उनकी मौत राजा की तरह हुई। उनलोगों ने राजा की तरह जीवन भी गुजारा।

संपादकीय

मुश्किल है डगर

भारत के पड़ोसी देशों में भारत विरोधी हवा बनाने में चीन अब विशेष रुचि लेने लगा है। उसने श्रीलंका के साथ यही किया है लेकिन श्रीलंका के नेता कुछ अधिक समझदार हैं सो वे भारत के साथ भी रिश्तों को अहमियत देते हैं। नेपाल के नेता चीन की गिरफ्त में इस कदर आ चुके हैं कि भारत के लिए उन्हें चीन के चंगुल से निकालना काफी मुश्किल होगा। सड़क और रेल संपर्क का सपना दिखा कर चीन पहले ही नेपाल को लुभा रहा है कि पेट्रोल और अन्य जरूरी सामान के लिए उसे भारत पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। नेपाली राजनेता अपनी कुर्सी की खातिर देश को नुकसान पहुंचाने वाली राजनीति कर रहे हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री ओली को नेपाली असेंबली में सफाई देनी पड़ी कि वह किसी विदेशी राजदूत की कृपा से नहीं बल्कि नेपाली जनता के प्रतिनिधि की हैसियत से सरकार चला रहे हैं और उनकी कुर्सी उनसे कोई नहीं छीन सकता। चीनी राजदूत ने नेपाल की राजनीति में अपने दबदबे का संकेत दो सप्ताह पहले दिया था जब उन्होंने काठमांडू में नेपाली राजनेताओं को एक असामान्य बैठक में बुलाकर कहा कि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के खिलाफ विद्रोह न करें। चीनी राजदूत की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री प्रचंड जैसे राष्ट्रीय नेता भी शामिल थे जिन्हें अपने अस्तित्व का संकट झेलना पड़ रहा है। इसलिए उन्होंने चीनी राजदूत की बात मान ली। साफ है कि चीनी राजदूत का नेपाली राजनेताओं पर दबदबा इतना बढ़ गया है कि वह नेपाली राजनीतिज्ञों को निर्देश दे सकते हैं कि सरकार कैसे और किसकी अगुवाई में चलानी है। इसी का नतीजा है कि नेपाली प्रधानमंत्री ने लिपुलेख दर्दा के आसपास के इलाके को अपना इलाका कहा तो उसे भी कोई अंकों आपको आगे बढ़ावा देने की रुचि नहीं दिखाई दी। इसी का कानून है।

चूंकि इस नदी धारा के उत्तर के इलाकों का सुगौली संधि में निर्धारण नहीं किया गया था, इसलिए कालापानी के इस इलाके पर प्रशासनिक व राजस्व नियंत्रण भारतीय प्रशासन का ही चला आ रहा है।

पुराना है सीमा विवाद

रंजीत कुमार।

तिब्बत के भीतर कैलाश मानसरोवर तक जाने के लिए पिथौरागढ़ होते हुए लिपुलेख के रास्ते 80 किलोमीटर की नई सड़क ने भारत और नेपाल के रिश्तों में मौजूद एक पुराने धाव को फिर से उधेड़ दिया है। भारत ने इस धाव को वक्त रहते नहीं भरा। इसी का नतीजा है कि नेपाल और भारत के रिश्तों में दरारें इतनी गहरी होने का खतरा उपस्थित हो गया है, जिसका इलाज काफी दर्द भरा होगा। इसमें कोई शक नहीं कि इसका फायदा चीन को मिलेगा क्योंकि इस विवाद से नेपाल में भारत विरोधी हवा और तेज चलेगी। इस मसले पर नेपाल में राजनीतिक आम राय बन चुकी है और भारत विरोधी प्रदर्शन होने लगे हैं।

भारत-चीन-नेपाल के त्रिकोण पर स्थित कालापानी-लिपुलेख इलाके पर भारत का प्रशासनिक और राजस्व अधिकार 19वीं सदी से ही रहा है। यह भी सही है कि 1816 में त्रिविश भारत और नेपाल के बीच हुई सुगौली संधि में महाकाली नदी के पश्चिम का इलाका त्रिविश भारत के तहत माना गया था। फिर 1923 की संधि में भी इन शर्तों को दोहराया गया था। नेपाली नेता भी कहते रहे हैं कि महाकाली नदी के पूर्व का इलाका नेपाल का है।



पर भी नदी के पश्चिम का इलाका भारत का होना चाहिए। लेकिन नेपाली लोगों ने बाद में महाकाली नदी के पश्चिम के इलाके को भी अपना बताना शुरू कर दिया। उनका कहना है कि महाकाली नदी लिपुलेख के उत्तर पश्चिम में लिंपियाधुरा की जलधारा से निकलती है। इसलिए कालापानी, लिंपियाधुरा और लिपुलेख का इलाका नेपाल के भीतर होगा। दूसरी ओर भारत की दलील है कि महाकाली नदी लिपुलेख दर्दा के निचले इलाके से निकलती है और चंकि इस नदी धारा के उत्तर के इलाकों का सुगौली संधि में निर्धारण नहीं किया गया था, इसलिए कालापानी के इस इलाके पर प्रशासनिक व राजस्व नियंत्रण भारतीय प्रशासन का ही चला आ रहा है।

यह विवादित मसला आपस में राजनीतिक स्तर

पर सुलझाने का भरोसा भारत की ओर से नेपाल को दिया जाता रहा है। सन 2000 में प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने भी तत्कालीन नेपाली प्रधानमंत्री जीपी कोईसाता को भरोसा दिया था कि 2002 तक भारत-नेपाल सीमा का निर्धारण हो जाएगा। जाहिर है ऐसा नहीं हो सका, जिससे हालात और बिगड़ते ही गए। दरअसल यह इलाका सामरिक नजरिये से काफी अहम है। इसी वजह से कैलाश मानसरोवर जाने के लिए 80 किलोमीटर लंबी सड़क का उद्घाटन हुआ तो चीन सहम गया क्योंकि इस सड़क मार्ग से होकर तिब्बत के भीतर तक भारतीय सेन्य आवाजाही आसानी हो जाएगी।

हालांकि चीन ने कहा है कि यह मसला भारत और नेपाल क